1. कॉपीराइट अधिनियम, 1957

1.1. कॉपीराइट क्या है?

- कॉपीराइट एक कानूनी शब्द है जिसका उपयोग **रचनाकारों के साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर उनके अधिकारों का वर्णन** करने के लिए किया जाता है।
- कॉपीराइट के दायरे में आने वाले कार्यों में किताबें, संगीत, पेंटिंग, मूर्तिकला और फिल्मों से लेकर कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्र तक शामिल हैं।

1.2. भारत में कॉपीराइट कानून

- कॉपीराइट अधिनियम, 1957 **कॉपीराइट नियम, 2013 के साथ,** भारत में कॉपीराइट संरक्षण से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है।
- कॉपीराइट अधिनियम लेखक को कार्य को पुन: प्रस्तुत करने, प्रतियां जारी करने, प्रदर्शन करने या इसे जनता तक संप्रेषित करने का आर्थिक अधिकार प्रदान करता है।
- यह किसी भी सिनेमैटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग को बनाने या काम का कोई अनुकूलन या अनुवाद करने का अधिकार भी प्रदान करता है।
- 1957 से कानून में छह बार संशोधन किया गया है और सबसे हालिया संशोधन 2012 में कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से किया गया था।

1.3. कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धाराएँ

- **धारा 13:** कॉपीराइट संरक्षण साहित्यिक कार्यों, नाटकीय कार्यों, संगीत कार्यों, कलात्मक कार्यों, सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग पर प्रदान किया जाता है।
- **नोट:** कंप्यूटर प्रोग्राम को अधिनियम के तहत साहित्यिक कार्यों के रूप में संरक्षित किया गया है।
- **धारा 2:** इसमें कार्य की विभिन्न परिभाषाएँ शामिल हैं जिन्हें कॉपीराइट की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।
- **धारा 14:** यह कॉपीराइट स्वामी को विशिष्ट अधिकारों का एक सेट प्रदान करता है। इन अधिकारों में अनुकूलन का अधिकार, पुनरुत्पादन का अधिकार, प्रकाशन का अधिकार, अनुवाद करने का अधिकार आदि शामिल हैं।
    - अधिकारों का प्रयोग केवल कॉपीराइट के स्वामी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके पास कॉपीराइट के स्वामी द्वारा इस संबंध में विधिवत लाइसेंस प्राप्त है।
- **धारा 17:** किसी कार्य का लेखक कॉपीराइट का पहला स्वामी होगा।
- **धारा 19:** भारत में कॉपीराइट के असाइनमेंट के तरीके बताता है। असाइनमेंट केवल लिखित रूप में हो सकता है और इसमें कार्य, असाइनमेंट की अवधि और वह क्षेत्र जिसके लिए असाइनमेंट किया गया है, निर्दिष्ट होना चाहिए।

1.4. दो प्रकार के अधिकार

कॉपीराइट अधिनियम, 1957, कॉपीराइट सुरक्षा को दो रूपों में प्रदान करता है: आर्थिक अधिकार और नैतिक अधिकार।

आर्थिक अधिकार

- आर्थिक अधिकार सही मालिकों को दूसरों द्वारा उनके कार्यों के उपयोग से वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।
- कॉपीराइट के लेखक कॉपीराइट अधिनियम की **धारा 14 के तहत** आर्थिक अधिकारों का उपयोग लेते हैं। अधिकार मुख्य रूप से साहित्यिक, नाटकीय और संगीत के संबंध में, कंप्यूटर प्रोग्राम के अलावा, किसी भी भौतिक रूप में काम को पुन: पेश करने के हैं।

नैतिक अधिकार

- नैतिक अधिकार लेखकों और रचनाकारों को अपने काम के साथ अपने संबंध को संरक्षित और रक्षित करने के लिए कुछ कार्रवाई करने की अनुमति देते हैं।
- एक लेखक के नैतिक अधिकारों को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की **धारा 57** में अभिव्यक्ति मिलती है। ये हैं: पितृत्व का अधिकार, और सत्यनिष्ठा का अधिकार।
- पितृत्व का अधिकार एक लेखक के काम के लेखकत्व का दावा करने के अधिकार और अन्य सभी को उसके काम के लेखकत्व का दावा करने से रोकने के अधिकार को संदर्भित करता है।
- सत्यनिष्ठा का अधिकार लेखक को उसके काम में किए गए किसी भी विरूपण, विकृति, संशोधन या किसी अन्य अप्रिय कार्य की स्थिति में नुकसान को रोकने या दावा करने की अनुमति देता है।

1.5. उल्लंघन के अपवाद

- कॉपीराइट अधिनियम, 1957 **धारा 52 के तहत** कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए कुछ अपवाद प्रदान करता है। निम्नलिखित कृत्य कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे, अर्थात्:
- किसी भी कार्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार, जो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए:
    - अनुसंधान सहित निजी या व्यक्तिगत उपयोग;
    - आलोचना या समीक्षा, चाहे वह उस कार्य की हो या किसी अन्य कार्य की;
    - वर्तमान घटनाओं और समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग, जिसमें सार्वजनिक रूप से दिए गए व्याख्यान की रिपोर्टिंग भी शामिल है।
- जनता के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन या संचार की तकनीकी प्रक्रिया में किसी कार्य या प्रदर्शन का क्षणिक या आकस्मिक भंडारण।
- न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजन के लिए या न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए किसी कार्य का पुनरुत्पादन।
- किसी विधानमंडल के सचिवालय द्वारा या जहां विधानमंडल में दो सदन होते हैं, वहां विधानमंडल के किसी भी सदन के सचिवालय द्वारा तैयार किए गए किसी भी कार्य का पुनरुत्पादन या प्रकाशन, विशेष रूप से उस विधानमंडल के सदस्यों के उपयोग के लिए।

- किसी भी कार्य का उस समय लागू किसी भी कानून के अनुसार बनाई या आपूर्ति की गई प्रमाणित प्रति में पुनरुत्पादन।
- किसी प्रकाशित साहित्यिक या नाटकीय कृति के उचित अंशों को सार्वजनिक रूप से पढ़ना या सुनाना।
- एक संग्रह में प्रकाशन, जो मुख्य रूप से गैर-कॉपीराइट सामग्री से बना है, निर्देशात्मक उपयोग के लिए प्रामाणिक है, और प्रकाशित साहित्यिक या नाटकीय कार्यों से छोटे अंशों के शीर्षक और प्रकाशक द्वारा या उसकी ओर से जारी किए गए किसी भी विज्ञापन में वर्णित है, स्वयं को ऐसे उपयोग के लिए प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें कॉपीराइट विद्यमान हो।

1.6. बर्न कन्वेंशन और कॉपीराइट अधिनियम 1957

- भारत साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए **बर्न कन्वेंशन, 1886 का एक हस्ताक्षरकर्ता है।**
- एक हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, भारत न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी किसी भी अनुबंधित राज्य में होने वाले कार्यों को समान सुरक्षा देने के लिए बाध्य है।
- बर्न कन्वेंशन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कॉपीराइट का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है।
- भारत में भी किसी के लिए कानून की सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए कॉपीराइट पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 भी पंजीकरण को अनिवार्य नहीं करता है।

1.7. कॉपीराइट (संशोधन) नियम, 2021

- ये संशोधन मौजूदा नियमों को अन्य प्रासंगिक कानूनों के बराबर लाने के उद्देश्य से पेश किए गए हैं।
- इसका उद्देश्य कॉपीराइट कार्यालय में संचार और कामकाज के प्राथमिक माध्यम के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को अपनाकर सुचारू और दोषरहित अनुपालन सुनिश्चित करना है।
- जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए, अवितरित रॉयल्टी राशि से निपटने और रॉयल्टी के संग्रह और वितरण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और ट्रेस करने योग्य भुगतान विधियों के उपयोग के लिए नए प्रावधान पेश किए गए हैं।
- पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए, कॉपीराइट समितियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए **वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट** तैयार करने और सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी।
- सॉफ़्टवेयर कार्यों के पंजीकरण के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को कम कर दिया गया है, अब आवेदक को स्रोत कोड के पहले 10 और अंतिम 10 पृष्ठ, या 20 पृष्ठों से कम होने पर संपूर्ण स्रोत कोड दाखिल करने की स्वतंत्रता है, जिसमें कोई अवरुद्ध या संशोधित भाग नहीं है।
- कॉपीराइट सोसायटी के रूप में पंजीकरण के लिए उसके समक्ष किए गए आवेदन पर प्रतिक्रिया देने के लिए केंद्र सरकार की समय सीमा एक सौ अस्सी दिन तक बढ़ा दी गई है, ताकि आवेदन की अधिक व्यापक जांच की जा सके।

2. भौगोलिक संकेत (Geographical Indication-GI)

2.1. भौगोलिक संकेत क्या है?

- भौगोलिक संकेत उन वस्तुओं पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी **एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति** होती है और उनमें ऐसे गुण, प्रतिष्ठा या विशेषताएं होती हैं जो **अनिवार्य रूप से उस मूल स्थान** (जैसे एक शहर, क्षेत्र या देश) **से संबंधित** होती हैं।
- भौगोलिक संकेत का उपयोग एक प्रमाणीकरण के रूप में कार्य कर सकता है कि उत्पाद में कुछ गुण हैं, पारंपरिक तरीकों के अनुसार बनाया गया है, या अपनी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण एक निश्चित प्रतिष्ठा प्राप्त है।

2.2. GI को मान्यता देने की आवश्यकता क्यों है?

- प्रत्येक क्षेत्र कुछ अनोखा होने का दावा करता है और कुछ स्थानीय उत्पाद उनकी प्रसिद्धि का दावा करते हैं। क्षेत्र की यह प्रतिष्ठा एक दिन में नहीं बनी है।
- ये अनूठे उत्पाद मनुष्य और प्रकृति के सर्वोत्तम गुणों का संयोजन हैं और इन्हें सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है और पीढ़ियों के लिए सौंप दिया गया है।
- उत्पादों और स्थानों को जोड़ने वाली विशिष्ट पहचान का जश्न मनाने और पहचानने के लिए, GI टैग विकसित किया गया था।
- कई देशों में, कानून द्वारा GI को दी गई सुरक्षा ट्रेडमार्क और विशेष रूप से प्रमाणन चिह्नों को दी गई सुरक्षा के समान है।
- भौगोलिक संकेत कानून की मांग है कि GI का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र से उत्पन्न होता है और/या कुछ मानकों को पूरा करता है।
- कभी-कभी ये कानून यह भी निर्धारित करते हैं कि उत्पाद को कुछ गुणवत्ता परीक्षणों को पूरा करना होगा जो एक ऐसे संघ द्वारा प्रशासित होते हैं जिसके पास लाइसेंस का विशेष अधिकार होता है या संकेत के उपयोग की अनुमति होती है।

2.3. विश्व स्तर पर कानूनी स्थिति

- TRIPS पर WTO समझौता "भौगोलिक संकेतों" को उन संकेतों के रूप में परिभाषित करता है जो किसी वस्तु की पहचान "किसी सदस्य के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले के रूप में करते हैं, जहां किसी वस्तु की दी गई गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य विशेषता अनिवार्य रूप से उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण होती है।"
- 1994 में, जब WTO TRIPS पर बातचीत संपन्न हुई, तो सभी WTO सदस्य देशों की सरकारें **सभी सदस्य देशों में GI की सुरक्षा के लिए** कुछ बुनियादी मानक निर्धारित करने पर सहमत हुईं।
- TRIPS समझौते के **अनुच्छेद 22 में** कहा गया है कि सभी सरकारों को उस देश में पंजीकृत GI के मालिक के लिए अपने स्वयं के कानूनों में **कानूनी अवसर प्रदान करना चाहिए** ताकि सामान की भौगोलिक उत्पत्ति के बारे में जनता को गुमराह करने वाले चिह्नों के उपयोग को रोका जा सके।

- TRIPS समझौते के **अनुच्छेद 23 में** कहा गया है कि सभी सरकारों को GI के मालिकों को अपने कानूनों के तहत, भौगोलिक संकेत द्वारा इंगित स्थान पर उत्पन्न न होने वाली वाइन की पहचान करने वाले भौगोलिक संकेत के उपयोग को रोकने का अधिकार प्रदान करना चाहिए।
- इसके अलावा, बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के महत्व को **पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) और 10** में स्वीकार किया गया है और इस पर जोर दिया गया है।

2.4. भारत में कानूनी स्थिति

- भारतीय संसद ने **दिसंबर 1999 में वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम** पारित किया (सितंबर 2003 में प्रभावी हुआ) जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं के पंजीकरण और GI की सुरक्षा प्रदान करना था।
- यह अधिनियम **पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक** (CGPDTM-Controller General of Patents, Designs and TradeMarks) द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो भौगोलिक संकेतों के रजिस्ट्रार भी हैं।
    - **नोट:** DPIIT के तहत CGPDTM को भारत में पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- कोई भी स्थापित संगठन या प्राधिकरण कानून के तहत GI टैग के लिए आवेदन कर सकता है।
- भौगोलिक संकेतों के तहत, जो व्यक्ति क्षेत्र विशेष के लिए कृषि वस्तुओं, प्राकृतिक वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, व्यापार या हस्तशिल्प या औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण, व्यापार या लेनदेन से संबंधित हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है।
- GI के तहत उत्पाद का पंजीकरण बेहतर कानूनी सुरक्षा की सुविधा प्रदान करता है और अधिकृत उपयोगकर्ता टैग का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के अपने अधिकार का उपयोग कर सकता है।
- GI का पंजीकरण **10 वर्ष की अवधि के लिए वैध** होता है जिसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है। यदि GI का नवीनीकरण नहीं कराया गया तो उसे रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।
- पंजीकृत GI एक सार्वजनिक संपत्ति है जो सामग्री के उत्पादकों की होती है। इसका उपयोग लाइसेंसिंग, संकल्प, गिरवी आदि के लिए नहीं किया जा सकता है। अधिकृत डीलर के निधन के बाद उसके अधिकार का प्रयोग उत्तराधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

2.5. भारत से कुछ उदाहरण

राज्य	उत्पाद
आंध्र प्रदेश	अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी
	तिरुपति लड्डू
	एटिकोप्पाका खिलौने

	उदयगिरि लकड़ी की नक्काशी
अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल नारंगी
	इदु मिश्मी टेक्सटाइल्स
असम	मुगा रेशम
	कार्बी आंगलोंग अदरक
	जोहा चावल
बिहार	शाही लीची
	मधुबनी पेंटिंग
	सिक्की घास उत्पाद
	मघई पान
छत्तीसगढ	बस्तर ढोकरा
	बस्तर लौह शिल्प
गोवा	फेनी
गुजरात	संखेड़ा फर्नीचर
	गिर केसर आम
	कच्छ शॉल
हिमाचल प्रदेश	कुल्लू शॉल
	कांगड़ा चाय
	हिमाचली काला ज़ीरा
	मैसूर सिल्क

कर्नाटक	चन्नापटना खिलौने और गुड़िया
	उडुपी साड़ी
	कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी
	मैसूर चंदन का तेल
केरल	अलेप्पी कयर
	नवारा चावल
	अल्लेप्पी हरी इलायची
	नीलांबुर सागौन
	स्क्रू पाइन क्राफ्ट
मध्य प्रदेश	चंदेरी साड़ी
	झाबुआ कड़कनाथ काला चिकन
	रतलामी सेव
महाराष्ट्र	सोलापुर चादर
	नासिक वैली वाइन
	पैठणी साड़ियाँ और कपड़े
	कोल्हापुर गुड़
	अलफांसो
मणिपुर	चक-हाओ
	कचाई नींबू
	मिज़ो मिर्च

मिजोरम	पॉन्डम
नगालैंड	नागा मिर्चा
ओडिशा	कोटपैड हथकरघा कपड़ा
	कोणार्क पत्थर नक्काशी
	ओडिशा रसगुल्ला
राजस्थान	कोरा डोरिया
	मोलेला मिट्टी का काम
	बीकानेरी भुजिया
तमिलनाडु	सलेम कपड़ा
	अरुम्बावुर लकड़ी की नक्काशी
	महाबलीपुरम पत्थर मूर्ति
	तंजावुर कला प्लेट
	कांचीपुरम सिल्क
त्रिपुरा	त्रिपुरा रानी अनानास
तेलंगाना	निर्मल खिलौने और शिल्प
	आदिलाबाद डोकरा
	चेरियाल पेंटिंग
	लखनऊ चिकन हस्तकला
	मलिहाबादी दशहरी आम
	बनारस ब्रोकेड्स और साड़ियाँ

उतार प्रदेश	कालानमक चावल
	कन्नौज इत्र
	चुनार बलुआ पत्थर
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग चाय
	बांग्लार रसगुल्ला
	कुशमंडी का लकड़ी का मुखौटा

2.6. GI का महत्व

- GI टैग एक संकेत है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए निश्चित होता है। इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है।
- किसी उत्पाद को GI टैग प्राप्त करने के लिए, **उस सामान का उस क्षेत्र में उत्पादन या प्रसंस्करण** या तैयार किया जाना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि उत्पाद की विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा हो।
- GI टैग फायदेमंद है क्योंकि यह भारत में **भौगोलिक संकेतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।** यह पहचान पंजीकृत GI के दुरुपयोग को रोकने में मदद करती है।
- इसके अलावा, GI की कानूनी सुरक्षा से निर्यात को बढ़ावा मिलता है। GI टैग न केवल देश के निर्यात बाजार को मदद करता है बल्कि उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने में भी मदद करता है।

3. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001

3.1. परिचय

- भारत सरकार ने पौधा प्रजनन गतिविधि में वाणिज्यिक पौधा प्रजनकों और किसानों दोनों के योगदान को मान्यता देने के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights-PPV&FR) अधिनियम, 2001 लागू किया। इसके लिए नियम **2003 में अधिसूचित** किए गए थे।
- यह कानून पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for the Protection of New Varieties of Plants-UPOV), 1978 के अनुरूप है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रजनन संस्थानों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं।
- **अधिनियम TRIPS समझौते का भी समर्थन करता है।** TRIPS समझौते के तहत, भारत नई पौधों की विविधता की सुरक्षा के लिए एक प्रणाली शुरू करने के लिए बाध्य था।

- समझौते ने सदस्य के लिए नई पौधों की किस्मों को पेटेंट या प्रभावी *सुई जेनेरिस* प्रणाली या इन दोनों के संयोजन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य बना दिया।

3.2. प्लांट ब्रीडर को अधिकार क्यों दिए जाएं?

- कृषि, बागवानी और वानिकी में सतत प्रगति प्रदान करने के लिए पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए प्रोत्साहन के रूप में पौधा प्रजनकों को संरक्षण प्रदान किया जाता है।
- किसानों और उत्पादकों के लिए उत्पादकता, गुणवत्ता और विपणन क्षमता में सुधार के लिए उन्नत किस्में एक आवश्यक और बहुत लागत प्रभावी साधन हैं।
- पौधों की नई किस्मों के प्रजनन के लिए कौशल, श्रम, भौतिक संसाधनों, धन और समय के मामले में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।
- बेहतर किस्मों के साथ नई किस्मों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करने का अवसर सफल पौधा प्रजनकों को अपनी लागत वसूलने और आगे के निवेश के लिए आवश्यक धन जमा करने का मौका प्रदान करता है।
- पादप प्रजनकों के अधिकारों के अभाव में, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना अधिक कठिन है क्योंकि प्रजनक की विविधता को बढ़ाने और उसे व्यावसायिक पैमाने पर बेचने से दूसरों को कोई रोक नहीं सकता है।

3.3. PPV & FR अधिनियम, 2001 के उद्देश्य

- नई पौधों की किस्मों के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना।
- घरेलू और विदेशी निवेश के माध्यम से देश में बीज उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाना। इससे भारतीय किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- कृषकों और संरक्षकों के रूप में किसानों की भूमिका और देश की कृषि जैव विविधता में पारंपरिक, ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के योगदान को मान्यता देना और लाभ साझा करने और पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के माध्यम से उनके योगदान के लिए उन्हें पुरस्कृत करना।

3.4. PPV & FR अधिनियम, 2001 के तहत पंजीकृत किस्में

- एक नई किस्म यदि नवीनता, विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता के मानदंडों के अनुरूप है।
- एक मौजूदा किस्म यदि यह विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता के मानदंडों के अनुरूप है।

3.5. PPV & FR अधिनियम, 2001 के तहत अधिकार

- **प्रजनकों के अधिकार:** संरक्षित किस्म का उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात या निर्यात करने के विशेष अधिकार।
- **शोधकर्ताओं के अधिकार:** प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए किसी भी पंजीकृत किस्म का उपयोग करना।

- **किसानों के अधिकार:** किसानों द्वारा उत्पादित किस्म को प्रजनक किस्म या मौजूदा किस्म के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। एक किसान अधिनियम के तहत संरक्षित किस्म के बीज सहित अपने कृषि उत्पाद को बचा सकता है, उपयोग कर सकता है, बो सकता है, दोबारा बो सकता है, विनिमय कर सकता है, साझा कर सकता है या बेच सकता है।
    - किसान मान्यता और पुरस्कार के साथ-साथ मुआवजे के भी पात्र हैं।
    - अधिनियम के तहत प्राधिकरण या रजिस्ट्रार या ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी कार्यवाही में किसान किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

3.6. PPV & FR अधिनियम, 2001 का कार्यान्वयन

- अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने **11 नवंबर, 2005 को पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण** की स्थापना की।
- अध्यक्ष प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी होता है।
- प्राधिकरण का उद्देश्य पौधों की किस्मों, किसानों और पौधा प्रजनकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना और पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना और बीज उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाना है।
- प्राधिकरण देश में कृषि विकास में तेजी लाने और नई पौधों की किस्मों के विकास के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम करता है।

4. राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016

4.1. परिचय

- राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights-IPR) नीति 2016 को देश में IPR के भविष्य के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक विज़न दस्तावेज़ के रूप में 12 मई, 2016 को अपनाया गया था।
- यह नीति भारत में प्रवाहित होने वाली रचनात्मक और नवीन ऊर्जा की प्रचुरता को पहचानती है, और इन ऊर्जाओं को सभी के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में लगाने की आवश्यकता को स्वीकार करती है।
- यह नीति IP के सभी रूपों को कवर करती है, उनके और अन्य एजेंसियों के बीच तालमेल बनाने का प्रयास करती है, और कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करती है।

4.2. नीति का मिशन

भारत में एक गतिशील, जीवंत और संतुलित बौद्धिक संपदा अधिकार प्रणाली को प्रोत्साहित करना, और:

- रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देना और इस प्रकार, उद्यमिता को बढ़ावा देना और सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ाना, और
- महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी महत्व के अन्य क्षेत्रों के अलावा स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण तक पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना।

4.3. कार्यान्वयन

- वाणिज्य मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) भारत में IPR विकास के लिए नोडल विभाग है और DPIIT के तहत CIPAM नीति को लागू करने के लिए संदर्भ का एकमात्र बिंदु है।

4.4. नीति के उद्देश्य

- **IPR जागरूकता-आउटरीच और संवर्धन:** समाज के सभी वर्गों के बीच IPR के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना।
- **IPR का सृजन:** IPR के सृजन को प्रोत्साहित करना।
- कानूनी और विधायी ढांचा: मजबूत और प्रभावी IPR कानून बनाना, जो बड़े सार्वजनिक हित के साथ अधिकार मालिकों के हितों को संतुलित करें।
- **प्रशासन और प्रबंधन:** सेवा उन्मुख IPR प्रशासन को आधुनिक और मजबूत बनाना।
- **IPR का व्यावसायीकरण:** व्यावसायीकरण के माध्यम से IPR का मूल्य प्राप्त करना।
- **प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन:** IPR उल्लंघनों से निपटने के लिए प्रवर्तन और न्यायनिर्णयन तंत्र को मजबूत करना।
- **मानव पूंजी विकास:** IPR में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कौशल निर्माण के लिए मानव संसाधनों, संस्थानों और क्षमताओं को मजबूत और विस्तारित करना।

IPR जागरूकता योजना - क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया

- राष्ट्रीय IPR नीति 2016 को आगे बढ़ाते हुए, एक 'IPR जागरूकता योजना - क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया' सेल फॉर IPR प्रमोशन एंड मैनेजमेंट (Cell for IPR Promotion and Management-CIPAM) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- योजना की अवधि 3 वर्ष (अप्रैल 2017 – मार्च 2020) थी।
- योजना का लक्ष्य देश भर में उद्योग संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के सहयोग से IP जागरूकता कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करना था।
- इसने प्रशिक्षकों का एक संसाधन पूल बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा जो जनता, प्रवर्तन एजेंसियों और न्यायपालिका के लिए IP जागरूकता कार्यशालाओं/सेमिनारों का संचालन करेगा।